History 6th Paper
B.A III Year

असहयोग आन्दोलन के परिणाम या प्रभाव :-

महात्मा गाँधी के नेतृत्व में फरवरी 1922 में चौरा चौरी काण्ड की प्रतिक्रिया स्वरूप से आन्दोलन बन्द कर दिये जाने से, प्रत्यक्ष रूप से चार परिणाम सामने आए -

① ब्रिटिश साम्राज्यियों का नग्न आक्रमण तेज :-

राष्ट्रीय आन्दोलन की माँग थी कि भारत में सरकारी नौकरियों में भारतीयों को लिया जाए लेकिन 1922 के चुनाव के बाद ब्रिटिश प्रधान मंत्री लायड जॉर्ज ने घोषणा की थी कि सरकारी पदों की रीढ़ अंग्रेजों को होना चाहिए। 1925 में भारत सचिव बर्कनहेड ने लॉर्ड्स सभा में कहा था - "हम बेचैन अधीर लोगों की लोगों से अपने उच्च कर्तव्य का रास्ता न छोड़ेंगे। वेगवृद्धि का दरवाजा धमकी से खुलने वाला नहीं। उस पर धावा बोलने से, हिंसा के जरिये, वह और भी कम खुलेगा।"

ब्रिटिश राजनेताओं के वक्तव्यों से यह स्पष्ट हो गया था कि आन्दोलन के बावजूद हिन्दुस्तान को अंग्रेज अपना उपनिवेश बनाये रखेंगे। ब्रिटिश शासक 1919 के भारत सरकार कानून के अनुसार बनी विधान सभाओं के फैसलों का भी सम्मान नहीं करते थे। नरेन्द्र मण्डल के अनुरोध पर भारत सरकार ने 1922 में विधान सभा में विद्रोह कराने के प्रयत्नों से देशी रियासतों की रक्षा के लिए एक विधेयक पेश किया। इसे बाद में कानून का रूप दिया गया। 1923 में नमक कर दूना कर दिया गया। इसके लिये वाइसराय ने असाधारण क्षमता का प्रयोग किया था।

25 अक्टूबर 1924 को वाइसराय लॉर्ड रीडिंग ने फरमान नम्बर 1 जारी कर बंगाल के अधिकारियों को पूरा अधिकार दिया कि वे आम अदालती कार्यवाही किए बिना ही किसी भी देशभक्त को दण्ड दे सकते थे। इस फरमान के तहत बंगाल के सिर्फ राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी (आतंकवादी) ही नहीं,

सुभाषचन्द्र बोस जैसे कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया।

अब कांग्रेसी नेता भी यह अनुभव करने लगे थे कि 1919 अधिनियम ने वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं दिया था। सारी शक्ति तथा क्षमता वाइसराय तथा गवर्नरों के हाथ में थी। इन अनुभवों का परिणाम यह हुआ कि बड़े-बड़े माडरेट नेताओं में भी असन्तोष फैल गया और वे इसके परिवर्तन की माँग करने लगे।

② साम्प्रदायिक दंगों का व्यापक विस्फोट :-

असहयोग आन्दोलन के अचानक रोक दिये जाने से साम्प्रदायिक तनाव अचानक बढ़ने लगा। क्रान्ति की शक्तियों को ध्वंस करने के लिये साम्राजियों ने साम्प्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा दिया और उनके जरिये बड़े-बड़े दंगे करवाये। 1923 से लेकर 1928 तक के प्रायः छः वर्ष बड़े साम्प्रदायिक दंगों से भरे हैं।

राष्ट्रीय आन्दोलन ने जब जोर पकड़ना शुरू किया था, ब्रिटिश शासकों ने तभी खासकर हिन्दुओं और मुसलमानों को मजहबी सवालों पर लड़ाकर अपना स्वार्थ साधने की कोशिश की थी। जब तक आन्दोलन उग्र रहा, अंग्रेजों की "फूट डालो और राज करो" नीति नाकाम रही, किन्तु आन्दोलन बन्द होते ही दंगे शुरू होने लगे।

1922 में आन्दोलन अचानक बन्द कर दिये जाने से कांग्रेस-खिलाफत-मैत्री समाप्त हो गयी। खिलाफत कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया कि लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता माना जाए। खिलाफत वाले आन्दोलन रोके जाने से कांग्रेस तथा गाँधी से रुष्ट हो गये थे। उनके क्रोध को ब्रिटिश राज नेताओं एवं उनके दलालों ने हिन्दुओं के खिलाफ मोड़ कर दंगों को भड़काया।